The Free Press Journal (Mumbai) 29 January, 2018

Rural bias to be prominently visible in Budget: Report

Left with squeezing fiscal space due to rising crude oil prices, looming uncertainty over GST collections, the last full Budget of the NDA Government would most likely be hugely rural –focussed, though middle class tax-payers may be offered some saving sops in small measures, even as the Finance Minister Arun Jaitley would have to heavily bank on the non-tax receipts, an ASSOCHAM Budget Paper has said.

"Both Prime Minister Narendra Modi and Finance Minister Arun Jaitley have given enough indications about what is going on in their mind about the way , the Budget for 2018-19 should pan out. They want rural India to be at the forefront of the development agenda and we would expect several initiatives in the direction of improving market access for farmers, micro irrigation, rural housing, rural roads and further financial inclusion," the report stated.

Prayukti

29 January, 2018

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नए अवसर लाएगा आम बजट

नई दिल्ली। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (एसोचैम) के मुताबिक आगामी आम बजट से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार अपने एजेंडे में ग्रामीण भारत को विकास की कमान सौंपना चाहती है। एसोचैम का कहना है कि कच्चे तेल की आसमान छूती कीमत और वस्तु एवं सेवा कर संग्रह को लेकर जारी अनिश्चितता के कारण मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट संभवतः ग्रामीण क्षेत्रों पर ही ज्यादा जोर देने वाला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आगामी बजट को लेकर पर्याप्त संकेत दिए हैं। वे विकास एजेंडे में ग्रामीण इलाकों को तवज्जो देना चाहते हैं और हम इसी कारण किसानों की बाजार तक पहुंच आसान बनाने , सिंचाई प्रबंधन, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़कें और वित्तीय समावेश को बढ़ाने की दिशा में पहल किए जाने की उम्मीद कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में जहां कई क्षेत्रों और लोगों की अलग-अलग जरुरतों का दबाव सार्वजनिक संसाधनों पर हैं और जीएसटी से राजस्व प्राप्ति की तस्वीर अभी स्पष्ट नहीं है, वहां उम्मीदों को वास्तविकता की धरातल पर रखना होगा। इसके अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर, रियलटी आदि क्षेत्रों से जुड़ी कुछ नीतिगत घोषणाएं बजट में की जा सकती है और इसका असर अप्रत्यक्ष कर भी पड़ सकता है।

इंफ्रास्ट्रक्चर, रियलटी आदि क्षेत्रों से जुड़ी नीतिगत घोषणाएं बजट में हो सकती हैं और अप्रत्यक्ष कर पर इसका सीधा असर पड़ सकता है।

ASSOCHAM IN THE NEWS

Naya India **29 January, 2018**

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नये अवसर लायेगा आम बजट:एसोचैम

नई दिल्ली, वार्ता। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (एसोचैम) के मुताबिक आगामी आम बजट से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार अपने एजेंडे में ग्रामीण भारत को विकास की कमान सौंपना चाहती है।

औद्योगिक संगठन के मुताबिक आगामी बजट 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की प्रक्रिया को शुरू करेगा। प्रधानमंत्री ने किसानों की आय बढाने के संबंध में प्रतिबद्धता जाहिर की थी और बजट में यह प्रतिबद्धता दिखेगी। एसोचैम का कहना है कि कच्चे तेल की आसमान छूती कीमत और वस्तु एवं सेवा कर संग्रह को लेकर जारी अनिश्चितता के कारण मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट संभवतः ग्रामीण क्षेत्रों पर ही ज्यादा जोर देने वाला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आगामी बजट को लेकर पर्याप्त संकेत दिये हैं। वे विकास एजेंडे में ग्रामीण इलाकों को तवज्जो देना चाहते हैं और हम इसी कारण किसानों की बाजार तक पहुंच आसान बनाने , सिंचाई प्रबंधन, ग्रामीण आवास,ग्रामीण सड़कें और वित्तीय समावेश को बढाने की दिशा में पहल किये जाने की उम्मीद कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में जहां कई क्षेत्रों और लोगों की अलग-अलग जरुरतों का दबाव सार्वजनिक संसाधनों पर हैं और जीएसटी से राजस्व प्राप्ति की तस्वीर अभी स्पष्ट नहीं है, वहां उम्मीदों को वास्तविकता की धरातल पर रखना होगा। संगठन का कहना है कि इस बार बजट में भारतीय उद्योगों के लिए कोई बड़ी घोषणा संभवतः न हो जबकि मध्यम आय वर्ग के करदाता को हल्की राहत मिले लेकिन यह बजट कोई ब्लॉक बस्टर नहीं होगा। संगठन के अनुसार अगले कुछ दिनों में जारी किया जाने वाला आम बजट शेयर बाज़ार की रिकॉर्ड तेजी का लाभ उठाकर किये गये पीएसयू इक्विटी के विनिवेश और घरेलू निवेशकों द्वारा म्युच्युअल फंड के माध्यम से और विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा इक्विटी में किये गये निवेश पर अधिक निर्भर करेगा।

ASSOCHAM IN THE NEWS

Shah Times **29 January, 2018**

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नए अवसर लाएगा आम बजट: एसोचैम

नई दिल्ली। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (एसोचैम) के मुताबिक आगामी आम बजट से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार अपने एजेंडे में ग्रामीण भारत को विकास की कमान सौंपना चाहती है। औद्योगिक संगठन के मुताबिक आगामी बजट 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की प्रक्रिया को शुरू करेगा। प्रधानमंत्री ने किसानों की आय बढाने के संबंध में प्रतिबद्धता जाहिर की थी और बजट में यह प्रतिबद्धता दिखेगी। एसोचैम का कहना है कि कच्चे तेल की आसमान छूती कीमत और वस्तु एवं सेवा कर संग्रह को लेकर जारी अनिश्चितता के कारण मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट संभवत: ग्रामीण क्षेत्रों पर ही ज्यादा जोर देने वाला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आगामी बजट को लेकर पर्याप्त संकेत दिए हैं। वे विकास एजेंडे में ग्रामीण इलाकों को तवज्जो देना चाहते हैं और हम इसी कारण किसानों की बाजार तक पहुंच आसान बनाने, सिंचाई प्रबंधन, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़कें और वित्तीय समावेश को बढ़ाने की दिशा में पहल किए जाने की उम्मीद कर सकते हैं।

Deshbandhu

29 January, 2018

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नए अवसर लाएगा आम बजट : एसोचैम

आगामी बजट 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की प्रक्रिया को शुरू करेगा

नई दिल्ली, 28 जनवरी (एजेंसियां)। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (एसोचैम) के मुताबिक आगामी आम बजट से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार अपने एजेंडे में ग्रामीण भारत को विकास की कमान सौंपना चाहती है। औद्योगिक संगठन के मुताबिक आगामी बजट 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की प्रक्रिया को शुरू करेगा। प्रधानमंत्री ने किसानों की आय बढाने के संबंध में प्रतिबद्धता जाहिर की थी और बजट में यह प्रतिबद्धता दिखेगी। एसोचैम का कहना है कि कच्चे तेल की आसमान छूती कीमत और वस्तु एवं सेवा कर संग्रह को लेकर जारी

वास्तव में विनिवेश वित्त् वर्ष 2018-19 की पहली छमाही में करना रणनीतिक रहेगा। इसके अलावा आधारभूत ढांचे, रेलवे और राजमार्गों में निवेश को बढाया जाएगा।

डीएस रावत, महासचिव, एसोचैम

अनिश्चितता के कारण मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट संभवतः ग्रामीण क्षेत्रों पर ही ज्यादा जोर देने वाला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आगामी बजट को लेकर पर्याप्त संकेत दिये हैं। वे विकास एजेंडे में ग्रामीण इलाकों को तवज्जो देना चाहते हैं और हम इसी कारण किसानों की बाजार तक पहुंच आसान बनाने, सिंचाई प्रबंधन, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़कें और वित्तीय समावेश को बढाने की दिशा में पहल किए जाने की उम्मीद कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में जहां कई क्षेत्रों और लोगों की अलग-अलग जरुरतों का दबाव सार्वजनिक संसाधनों पर हैं व जीएसटी से राजस्व प्राप्ति की तस्वीर अभी स्पष्ट नहीं है, वहां उम्मीदों को वास्तविकता की धरातल पर रखना होगा। संगठन का कहना है कि इस बार बजट में भारतीय उद्योगों के लिए कोई बड़ी घोषणा संभवतः न हो जबकि मध्यम आय वर्ग के करदाता को हल्की राहत मिले लेकिन यह बजट कोई ब्लॉक बस्टर नहीं होगा। संगठन के अनुसार अगले कुछ दिनों में जारी किया जाने वाला आम बजट शेयर बाजार की रिकॉर्ड तेजी का लाभ उठाकर किए गए पीएसयू इक्विटी के विनिवेश व घरेलू निवेशकों द्वारा मयुच्युअल फंड के माध्यम से और विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा इक्विटी में किए गए निवेश पर अधिक निर्भर करेगा। विनिवेश का लक्ष्य एक लाख करोड़ से अधिक का हो सकता है।

ASSOCHAM IN THE NEWS

Rajasthan Patrika **29 January, 2018**

एसोचैम...

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नए अवसर लाएगा बजट

नई दिल्ली @ पत्रिका. भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (एसोचैम) के मुताबिक आगामी आम बजट से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार अपने एजेंडे में ग्रामीण भारत को विकास की कमान सौपना चाहती है। औद्योगिक संगठन के मुताबिक आगामी बजट 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की प्रक्रिया को शुरू करेगा। प्रधानमंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने के संबंध में प्रतिबद्धता जाहिर की थी और बजट में यह प्रतिबद्धता दिखेगी।

एसोचैम का कहना है कि कच्चे तेल की आसमान छूती कीमत और जीएसटी कर संग्रह को लेकर जारी अनिश्चितता के कारण मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट संभवतः ग्रामीण क्षेत्रों पर ही ज्यादा जोर देने वाला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आगामी बजट को लेकर पर्याप्त संकेत दिये हैं। वे विकास एजेंडे में ग्रामीण इलाकों को तवज्जो देना चाहते हैं।